POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 01 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 392 फुट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनी है। इसके लिए भारत के हर गांव से लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इकट्ठे हुए लोहे को पिघला कर यह प्रतिमा बनाई जाएगी। इस पुनीत योजना में आपके योगदान की आवश्यकता है।

सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका नाम 'सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट' है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों को एकजुट कर स्वतंत्रता आन्दोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। वे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृहमंत्री भी रहे। उनकी वजह से ही 600 देशी रियासतें भारत में एकजुट हो सकी थीं। देशहित में किए गए उनके साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें 'लौह पुरुष' कहा जाता है।

मेरा देश के सभी किसानों व ग्रामीण भाइयों से आग्रह है कि वे इस पुनीत काम के लिए लोहा इकट्ठा करें और उसे गुजरात भिजवाएं।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

अन्ना खुश: 46 साल से अटका लोकपाल बिल पास

आखिर संसद ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से लोकपाल बिल को पारित कर दिया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। पांच दशकों से अटके लोकपाल के लिए समाजसेवी अन्ना हजारे ने पिछले करीब तीन सालों से लगातार लड़ाई लड़ी है। उनके इस संघर्ष को अपार जनसमर्थन मिला है। बिल पारित होने पर उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल को राज्यों और अन्य निचले स्तरों पर भी लागू किया जाए। यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित होगा।

- विधेयक के अनुसार सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से की जा सकेगी। लोकपाल खुद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकेगा। भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के लिए एक साल की सजा का प्रावधान है।
- किसी भी अधिकारी की जांच करने के लिए लोकपाल खुद भी छापे मार सकता है। लोकपाल से जुड़े मामलों में सीबीआई लोकपाल के अधीन काम करेगी। जांच से जुड़े सीबीआई अफसरों का ट्रांसफर नहीं होगा। लोकपाल को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा।
- राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार राज्य विधानसभा के पास है। कानून बनने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य होगी। सभी श्रेणियों के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी इसके दायरे में है।
- प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है, हालांकि उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया होगी।

रोडवेज प्रशासन पर 18 हजार रुपए का जुर्माना

जयपुर स्थित श्याम नगर निवासी ओ.पी. वर्मा ने उपभोक्ता जिला मंच, जयपुर में राजस्थान रोडवेज के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि पारिवारिक काम से दिल्ली जाने के लिए वाल्वो बस के 3 टिकट लेकर वह अपनी पत्नी व ससुर के साथ बस में सवार हुए थे। उनसे प्रति यात्री 780 रुपए वसूले गए। टिकट पर लिखे अनुसार उन्हें बस में एसी, एलसीडी व पेन्ट्री सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जयपुर से कुछ दूर निकलते ही एसी बन्द हो गया और एलसीडी टीवी भी नहीं चलाया गया। सीट पुश करने पर पीछे न हुई। जब परिचालक से पूछा तो बताया गया कि सीट खराब है। उन्होंने सफर के बाद रोडवेज से क्लेम मांगा तो उन्हें मना कर दिया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने इसे रोडवेज की सेवा में कमी माना। मंच ने रोडवेज को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 18 हजार रुपए का हर्जाना दे। आदेश के खिलाफ रोडवेज ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई और कहा कि बस कार्यशाला से चैक कर भेजी गई थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन रोडवेज प्रशासन कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस पर राज्य आयोग ने उपभोक्ता जिला मंच के आदेश को बरकरार रखते हुए परिवादी को 15 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति व तीन हजार रुपए परिवाद खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं।

वसुंधरा राजे ने बनाई सरकार

'कट्स' द्वारा चुनाव पूर्व किए गए सर्वेक्षण में प्रदेश के लोगों ने राजस्थान में वसुंधरा राजे द्वारा सरकार बनाए जाने की राय व्यक्त की गई थी। विभिन्न जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों के 64 फीसदी लोगों ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के लिए पसन्द किया था और भाजपा को बहुत अच्छा बहुमत मिलने की उम्मीद जताई थी। उनकी सभी उम्मीदें सही साबित हुई हैं।

वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 200 में से 163 सीट जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस में केन्द्रीय स्तर तक फैला भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, एक के बाद एक सामने आए घोटाले, महिलाओं पर अत्याचार, जनलोकपाल बिल पारित नहीं करना आदि हार के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। प्रदेश में चुनाव से कुछ समय पहले की गई घोषणाएं और उनका हर दिन किया गया प्रचार-प्रसार भी मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि वह उनकी सभी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करेंगी।

बेहतरी के लिए करेंगे मेहनत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि वह राजस्थान की बेहतरी के लिए जी-तोड़ मेहनत करने का प्रयास करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। सरकार और उसके अधिकारियों, सिविल सोसायटी और जनता के तालमेल से ही सुखद परिवर्तन लाया जा सकता है।

राजे ने सोशल मीडिया पर प्रदेश की जनता के नाम एक सन्देश जारी करते हुए कहा है कि सुदृढ़ राजस्थान के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश की अनगिनत समस्याओं को समझना है। यह काम शुरू कर दिया गया है। बदलाव के लिए कुछ समय चाहिए। यह देश में बदलाव लाने का चुनाव है, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

मांगी योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी आईएएस अफसरों से उनके विभागों में चल रही प्रमुख योजनाओं, खास मुद्दों व पिछले पांच सालों में किए कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मांगा है।

इसमें ज्यादा जोर गहलोत सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं पर है। दरअसल, राजे सभी विभागों के लिए सौ दिन की कार्ययोजना तैयार करना चाहती है और इसी कड़ी में सभी विभागों से उनके यहां चल रहे कामकाज की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसके आधार पर सभी योजनाओं की जल्द ही समीक्षा की जाएगी।

किसानों को आठ घंटे बिजली

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बिजली कंपनियों ने किसानों को आठ घंटे बिजली देने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल, भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को 8 घंटे के ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की घोषणा की थी।

अब सरकार कभी भी आठ घंटे बिजली व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांग सकती है। मद्देनजर, कंपनियों के अधिकारी बिजली आपूर्ति के हिसाब से नये सिरे से कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं।

डिस्कॉम के उच्चाधिकारी, अभियंता और निजी सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि भी बिजली की मांग और आपूर्ति का लेखा-जोखा तैयार करने में जुटे हैं।

समूहों को कम ब्याज पर कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे महिला स्वयंसहायता समूहों को सात फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएं। केन्द्रीय बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आजीविका (एसजीएसवाई) स्कीम के तहत इन समूहों को कम दर पर ऋण दिया जाए।

जानी लोगों की वेदना

मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे ने आमजन से मिलना शुरू कर दिया। अपने निवास पर आयोजित पहली जनसुनवाई में वे पूरी तसल्ली से लोगों से मिली। किसी ने अपनी व्यक्तिगत समस्या बताई तो किसी ने अपने क्षेत्र की। अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

जैसे-जैसे लोगों ने अपनी वेदना और समस्याएं बताई वह अधिकारियों को उन्हें दूर करने का निर्देश देती गई कि समस्या का निदान कैसे करना है। लोगों का कहना था जैसा काम मुख्यमंत्री ने किया है, वैसा ही काम अब अधिकारी करेंगे तो इससे सरकार और आमजन के बीच दूरी कम हो सकेगी।

पशु विकास पर नहीं हुआ खर्च

पिछले पांच सालों से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड में कुप्रबंधन के चलते तीन करोड़ 34 लाख रुपए का उपयोग नहीं हुआ। यह राशि केन्द्र सरकार ने पशुधन विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की थी। यह राशि पशुपालकों तक पहुंचती तो उन्हें भी लाभ मिलता और दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती। अब यह राशि मजबूरन बोर्ड को केन्द्र सरकार को वापस लौटानी होगी।

यह ही नहीं बोर्ड के पास विकास निधि के तहत करीब 10 करोड़ रुपए जमा है। नियमानुसार इसमें से 85 फीसदी राशि का उपयोग किया जाना जरूरी था।

दवाओं की कीमतों में होगी कमी

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली 620 दवाएं 25 दिसम्बर के बाद सस्ती दर पर बिकने लगेंगी। देश में हर साल करीब 3 प्रतिशत लोग सिर्फ इलाज में लगने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

कोर्ट का यह फैसला आम लोगों के लिए काफी मददगार होगा। इस फैसले के असर से इनकी कीमत 40 से 90 फीसदी तक कम हो जाएंगी। 25 दिसम्बर के बाद यदि किसी मेडिकल स्टोर पर पुराना स्टॉक भी बचा होगा तो उसे सस्ते दाम पर ही बेचना होगा।

मरीज ले रहा है कैसी दवा?

मरीज कैसी दवा ले रहा है, यह जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय राजस्थान सहित देशभर में रेंडम सर्वे करेगा। इसके लिए प्रदेश के 19 जिलों का चयन किया गया है।

इस अभियान के तहत होलसेल, रिटेलर और सरकारी अस्पतालों से दवाई के सेम्पल लेकर उनकी जांच होगी। इससे पता लगेगा कि मरीज कैसी दवा ले रहा है। सैंपलों की कोलकाता की लेबोरेट्री में जांच होगी। यदि किसी दवा की गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी, तो दवा कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हक से मांगे सूचना

पहले केवल विधायक व सांसद ही विधानसभा या संसद के जरिए सूचनाएं मांग सकते थे, लेकिन अब हर व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांग सकता है। कई सरकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी नहीं होती है। इससे कई योजनाओं का लाभ वे लोग उठा लेते हैं, जो उसके हकदार नहीं हैं।

यदि हम सूचना के अधिकार का उपयोग करके जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों से समय-समय पर योजना की जानकारी लेते रहेंगे, तो योजनाओं में जो लूट होती है वह नहीं हो सकेगी। जरूरी सूचनाओं के लिए सभी लोग सक्रिय हों और आस-पास होने वाले कामों और सरकारी कार्यालयों पर नजर रखें व जानकारी मांगते रहें। - रामावतार गुप्ता, भीलवाड़ा

युवा वर्ग को है उम्मीद

वर्तमान में देश में रोजगार की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरों में ही नहीं गांवों में भी माता-पिता अब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को तवज्जह देने लगे हैं। पढ़ाई का खर्च भी कम नहीं होता। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो पारिवारिक समस्याएं गंभीर बन जाती हैं।

राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से पहले हजारों भर्तियां निकाली, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। ज्यादातर पर कोर्ट की भी रोक लगी है। इससे युवा वर्ग व उनके परिवारजन निराश हैं। यह कारण भी पूर्ववर्ती सरकार के लिए भारी पड़ा और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। युवा वर्ग को अब नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

- पंकज भारद्वाज, जोधपुर

बैसाखियों पर चलना ठीक नहीं

जातिवाद, धनबल, अपराधिक छवि और वोट की राजनीति ने देश को सुशासन नहीं दिया है। इससे छोटी-बड़ी सभी पार्टियां भ्रष्टाचार और स्वार्थ के दलदल में फंसी हैं। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। युवा वर्ग चाहता है राजनीतिक पार्टियां स्वच्छ हो, इसके लिए वे खुद सुधारात्मक कदम उठाएं, जनता के प्रति जवाबदेह बनें।

बैसाखियों पर चलना ठीक नहीं। सूचना का अधिकार विधायिका हो या न्याय-पालिका सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। गलत तरीकों से कमाई गई सम्पत्ति जब्त हो, न्याय शीघ्र मिले। खाली भर्तियों को जल्द भरा जाए। इस सोच को युवाशक्ति प्रभावशाली बना सकती है।

- डॉ. के.एम. शर्मा, एडवोकेट, पाली

जब्त हो आय से अधिक सम्पत्ति

आय से अधिक सम्पत्ति जब्त करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 को विधान सभा में पारित हुए सवा साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। पिछली सरकार की सुस्ती से कानून अमल में नहीं आ पाया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के कई मामले चिन्हित हैं। सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने में स्फूर्ति दिखाई होती, तो करोड़ों रुपए की सम्पत्ति स्कूल व अस्पताल आदि के लिए मिल सकती थी। अब नई सरकार को कानून को अमल में लाने के प्रति गंभीरता से कदम उठाना होगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485